www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp APRIL 2019

कमल संदेश

लोकसभा चुनाव 2019 विशेषांक

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का उत्थान

भारतीय जनता पार्टी

क्यों चाहिए मोदी सरकार

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

1. क्यों चाहिए मोदी सरकार 06
2. सेना और पूर्व सैनिकों के प्रति समर्पित मोदी सरकार 08
3. अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण 10
4. गरीब हमारी पहली प्राथमिकता 12
5. युवा- हमारा भविष्य 14
6. मध्यम वर्ग समाज की रीढ़ 16
7. छोटे उद्यमी स्वदेशी के ध्वजवाहक 18
8. महिला सशक्तिकरण 20
9. श्रमिक श्रमेव जयते 22
10. समृद्ध किसान - समृद्ध राष्ट्र 24
11. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का उत्थान 26
12. दिव्यांग हमारे विशिष्ट नागरिक 28
13. अल्पसंख्यक अब मुख्यधारा में 30
14. कृपया वोट देने से पहले सोचें 32

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

Chowkidar Narendra Modi @narendramodi

बचपन से सुनते आ रहे हैं– गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन कांग्रेस के राज में गरीबी सिर्फ बढ़ी। आज देश का गरीब कह रहा है- "कांग्रेस हटाओ, गरीबी अपने-आप हट जाएगी।"

Chowkidar Amit Shah @AmitShah

जब एक लोकप्रिय नेतृत्व के लिए ओछी और अपमानजनक भाषा का प्रयोग होता है, तो देशभर में से प्रतिक्रियाएं आना स्वाभाविक होता है। यह कांग्रेस अध्यक्ष और पूरे विपक्ष के द्वारा मोदी जी के बोले गये अपशब्दों का ही परिणाम है कि आज पूरा देश मोदी जी के साथ चौकीदार बनकर खड़ा हो गया है।

Chowkidar Piyush Goyal @PiyushGoyal

राहुल गांधी जी द्वारा गरीबों का मजाक बनाया जा रहा है, देश का गरीब पिछले 70 सालों की कांग्रेस की अक्षमता और भ्रष्टाचार के कारण प्रगति नही कर सका। आज भी हवाई वादें करके कांग्रेस उनकी गरीबी का उपहास कर अपनी राजनीति चमकाना चाहती है।

facebook

कांग्रेस और गठबंधन का भाजपा से विकास के कामों के मुद्दे पर कोई मुकाबला नहीं है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बनी हैं। 'सबका साथ, सबका विकास' के मूल पर भाजपा ने काम किया है। बिहार में और पूरे देश में माननीय श्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में एक लहर चल रही है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फिर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी।

— शिवराज सिंह चौहान

विगत 5 वर्षों में महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न योजनायें प्रारम्भ की हैं। जन्म से वृद्धावस्था व घरेलू उत्पादों से व्यवसाय तक की इन योजनाओं के ज़रिए से नए भारत में नई नारी शक्ति का उदय हुआ है।

— डॉ. रमन सिंह

समाज के हर वर्ग का हुआ विकास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में भाजपा नीत राजग सरकार ने पूरे देश में आशा एवं विश्वास का एक नया युग प्रारंभ किया है। हर क्षेत्र में उपलब्धियों का अंबार लगा हुआ है और देश के सर्वांगीण विकास के लिये अनुपम कार्य हुए हैं। कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार, कुशासन, पॉलिसी पैरेलिसिस, घपले एवं घोटालों के दौर से देश को निकाल आज विश्व पटल पर एक सशक्त एवं स्वाभिमानी राष्ट्र स्थापित करने का कठिन कार्य मात्र पांच वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुआ है। आज देश तीव्र विकास के पथ पर अग्रसर है और एक नये भारत का भव्य चित्र पूरे विश्व के सामने उभर रहा है।

पिछले पांच वर्षों में अनेक अभिनव योजनाओं के माध्यम से देश में जनकल्याण के व्यापक कार्यक्रम हुए हैं और उनका परिणाम अब पूरे देश के सामने है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हरेक योजना के केन्द्र में देश का गरीब से गरीब व्यक्ति और पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिया गया 'अंत्योदय' का मंत्र रहा है। गरीबों का आर्थिक समावेशन, उन्हें बिचौलियों से मुक्त करना, उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य, सस्ते अनाज, सस्ती दवाइयां और उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिये सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किये हैं। इसी तरह महिलाओं के लिए अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से उनका सशक्तिकरण हुआ है तथा विशेषकर गरीब महिलाओं के लिये शौचालय, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत धुएं से मुक्त रसोई, पक्के आवास एवं आवास में बिजली जैसे कार्य से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन के बीज डाले गए हैं। युवाओं को प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करा स्वरोजगारी की ओर प्रेरित कर एक नये युग का प्रारंभ किया गया है। किसानों की समृद्धि तथा 2012 तक उनका आय दुगुना करने के लिये उत्पादन लागत का डेढ़ गुना एमएसपी सुनिश्चित कर एवं किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 5 एकड़ जोत वाले कृषक को 6 हजार रुपये का वार्षिक सम्मान देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिये परिवर्तनकारी कदम उठाये गये हैं तथा उनके लिये नये अवसरों की संभावनाओं का निर्माण किया गया है। पहली बार किसी सरकार ने पूर्व सैनिकों की कई दशकों से चली आ रही 'वन रैंक, वन पेंशन' की मांग को पूरा किया है तथा उनके सम्मान एवं देश की सुरक्षा में अनेक बड़े कदम उठाये हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'दिव्यांग' शब्द देकर हमारे समाज के एक वर्ग की विशिष्टता एवं उनके योगदान को स्वीकारा है और उनके लिये अनेक नई व्यवस्थाओं का सूत्रपात किया है। देश के श्रमिक वर्ग, छोटे उद्यमी एवं लगभग समाज के हर वर्ग के लिये व्यापक परिवर्तन के कदम उठाये गये हैं।

पिछले पांच वर्षों में अनेक अभिनव योजनाओं के माध्यम से देश में जनकल्याण के व्यापक कार्यक्रम हुए हैं और उनका परिणाम अब पूरे देश के सामने है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हरेक योजना के केन्द्र में देश का गरीब से गरीब व्यक्ति और पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिया गया 'अंत्योदय' का मंत्र रहा है।

'कमल संदेश' का 'लोकसभा चुनाव 2019' का विशेषांक आपके हाथों में है। आज देश को 'क्यों चाहिए मोदी सरकार' से लेकर समाज के विभिन्न वर्गों के लिए किये गये कार्यों एवं प्रमुख उपलब्धियां इस अंक में है। आशा है इससे हमारे सुधी पाठकों को इस अंक से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के परिवर्तनकारी एवं दृढ़ नेतृत्व में किये जा रहे वृहत कार्यों की विस्तृत जानकारियां मिलेगी। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

क्यों चाहिए मोदी सरकार

"सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।
मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।।
मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे।
मेरा अंबर पूछ रहा, कब अपना धर्म निभाओगे।।
मैंने वचन दिया भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा,
सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा,
मैं देश नहीं झुकने दूंगा।"

– नरेन्द्र मोदी

1. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ऊरी आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक से तथा पुलवामा आतंकी हमले के बाद एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को सबक सिखाया।
2. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के मस्तक को ऊंचा करके विश्व में अग्रणी पंक्ति में बैठाया, भारतीयों और प्रवासी भारतीयों का गौरव बढ़ाया तथा वैश्विक मंचों से भारतीय संस्कृति का डंका बजाया।
3. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कराया।
4. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सामान्य वर्ग के गरीबों को दस प्रतिशत आरक्षण दिलाया। इससे करोड़ों युवा लाभान्वित होंगे, जो अभी तक आरक्षण के लाभ से वंचित थे।
5. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया।
6. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कुंभ के पवित्र स्थल पर सफाई कर्मचारियों के पांव धोकर उन्हें सम्मानित किया।
7. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित पांच स्थानों पर पंच तीर्थ का निर्माण कराया।
8. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को स्वच्छ करने के लिए स्वच्छता मिशन को जन आंदोलन बनाया और 10 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया।
9. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकों से अछूती 34 करोड़ जनसंख्या के खाते खुलवाकर उन्हें बैंकों से जुड़वाया।
10. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी राशि को सीधे लोगों के बैंक खाते में डलवा कर गरीबों को बिचौलियों से मुक्त कराया।
11. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने गुमनामी में पड़े सेना और पुलिस के शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय समर स्मारक तथा पुलिस मेमोरियल बनाया।
12. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यम वर्ग के लोगों को 5 लाख की आय तक इनकम टैक्स से छूट दिलवाने का निर्णय लिया।
13. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 'मुद्रा योजना' से ऋण देकर और कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण देकर युवाओं को स्वरोजगारी बनाया।
14. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब महिलाओं को उज्ज्वला के अन्तर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर धुएं से मुक्त कराया।
15. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने नवजात शिशुओं की कामकाजी माताओं को छह महीने का अवकाश वेतन सहित दिलाया।
16. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 6000 रुपये की वार्षिक सम्मान निधि देकर किसानों का सम्मान बढ़ाया।
17. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रतिवर्ष पेंशन दिलवाने की योजना का निर्माण कराया।
18. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे उद्यमियों को दिए जाने वाले ऋण की स्वीकृति मात्र 59 मिनट यानि एक घंटे से भी एक मिनट कम में करने का निर्देश दिया।
19. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व सैनिकों को 'वन रैंक– वन पेंशन' देकर अपना वायदा निभाया।
20. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अंधेरे में रह रहे 18,374 गांवों में बिजली पहुंचाकर उन्हें अंधेरे से मुक्त कराया।
21. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से बीमारों का मुफ्त इलाज करवाकर उनकी जिंदगी को बचाया। इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों के लगभग 50 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।
22. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने विकलांगों को दिव्यांग शब्द की संज्ञा देकर उनको विशिष्ट पहचान पत्र जारी करवाया।
23. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हज का कोटा बढ़ाकर 2 लाख हाजियों को हज यात्रा करने का प्रावधान करवाया।
24. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 21 जून के दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित करवाया।
25. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को अंतरिक्ष महाशक्ति बनाया।

सेना और पूर्व सैनिकों के प्रति समर्पित मोदी सरकार

"मैं चैन से सोता हूं क्योंकि तुम सरहद पर तैनात हो।
शीश झुकाएं पर्वत, अंबर और भारत का चमन तुझे।
उसी तरह सेनानी मेरा भी है, शत शत नमन तुझे।"

— नरेंद्र मोदी (मन की बात से उद्धृत)

1. **कृतज्ञ राष्ट्र का शहीदों को नमन–** शहीदों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए देश में 'राष्ट्रीय समर स्मारक' की स्थापना की गई है। गुमनामी के अंधेरे में अभी तक उपेक्षित रहे शहीदों के प्रति यह राष्ट्र द्वारा दी गई भावांजलि का प्रतीक है।

2. **वन रैंक–वन पेंशन की मांग पूरी–** दशकों पुरानी वन रैंक – वन पेंशन की मांग को पूरा करके सैनिकों को सम्मान दिया गया है। वन रैंक – वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को 35000 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं।

3. **रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक–** वर्ष 2019 में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकार ने पहली बार रक्षा क्षेत्र का बजट 3 लाख करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है।

4. **राफेल सौदे को स्वीकृति –** वर्षों से लंबित राफेल सौदे को स्वीकृति देकर वायुसेना की शक्ति में बढ़ोतरी की गई है।

5. **बुलेट प्रूफ जैकेटों की मांग पूरी–** सेना द्वारा वर्ष 2009 में की गई बुलेट प्रूफ जैकेटों की मांग को पूरा कर दिया गया है। एक लाख 86 हजार बुलेट प्रूफ जैकेटों की खरीद को स्वीकृति दे दी गई है।

6. **अब भारतीय वायु सेना में लड़ाकू पायलट के रूप में महिलाएं भी–** भारतीय वायु सेना में पहली बार भारतीय महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पायलट के रूप में शामिल किया गया है।

7. **अत्याधुनिक हथियारों की खरीद को स्वीकृति–** सेना के लिए अत्याधुनिक हथियारों की खरीद को भी स्वीकृति दी गई है।

8. **शस्त्र निर्माण में स्वदेशी क्षमता की वृद्धि –** अभी तक भारत विदेशों से आयातित शस्त्रों पर ही निर्भर था। अब हम स्वदेश में शस्त्र निर्माण की क्षमता की ओर तेज़ कदमों से आगे बढ़ रहे हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण

"दशकों से देश में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग हमारे पिछड़े भाई-बहन कर रहे थे। इस मांग को पूरा करने का काम भी इस सरकार ने किया है। अब ओबीसी कमीशन के पास जितनी जिम्मेदारियां हैं, उतने ही उचित अधिकार भी हैं।"

– नरेन्द्र मोदी

1. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्ज़ा –** अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण के लिए संविधान का संशोधन करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यह एक ऐतिहासिक, दूरदर्शी और अभूतपूर्व निर्णय है।

2. **ओबीसी के उत्थान हेतु आयोग की भूमिका में बदलाव–** इसके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर बनने वाली योजनाओं में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका में भी बदलाव किया गया है। यह आयोग अब सलाहकार नहीं, बल्कि भागीदार की भूमिका में होगा।

3. **ओबीसी वर्ग के लिए मैट्रिक से पहले छात्रवृत्ति हेतु आय सीमा में वृद्धि–** अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिक से पहले छात्रवृत्ति की पात्रता हेतु वार्षिक आय की सीमा 44,000 रुपए से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दी गई है। पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए आय पात्रता सीमा एक लाख से बढ़ा कर डेढ़ लाख प्रतिवर्ष कर दी गई है।

4. **फ्री- कोचिंग की पात्रता के लिए वार्षिक आय में वृद्धि–** ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए फ्री-कोचिंग हेतु वार्षिक आय की पात्रता 4 लाख 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है।

5. **पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना–** इस योजना के अंतर्गत सरकार के कार्यकाल में 153 करोड़ रुपए की राशि की लागत से 9,069 सीट की क्षमता के देश भर में छात्रों के लिए 86 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं।

6. **कौशल विकास योजना–** इस योजना के अंतर्गत मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछड़े वर्ग के 62,874 व्यक्तियों को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 69 करोड़ 79 लाख रुपए की धनराशि व्यय की गई है। प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों में से 31,822 व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त हुआ है।

7. **क्रीमी लेयर की आय सीमा में वृद्धि–** पहले 6 लाख रूपए से अधिक आय वाले लोगों को पिछड़ा वर्ग की सुविधाओं की पात्रता नहीं थी। अब 8 लाख रुपए तक की आय वाले लोग भी पिछड़ा वर्ग की सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र होंगे।

8. **पिछड़ा वर्ग के छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति के लाभ–** विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। अब तक 2 करोड़ 64 लाख छात्रों को 3,797 करोड़ 2 लाख रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है।

गरीब हमारी पहली प्राथमिकता

"वोट लेकर जनता को भूल जाना कुछ लोगों की आदत रही है। वो गरीब को गरीब बनाए रखना चाहते हैं ताकि पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी हटाओ के नारे लगा सकें। हम गरीब को इतनी ताकत दे रहे हैं कि वो अपनी गरीबी से तेजी से बाहर निकले। आज भारत में तेजी से गरीबी कम हो रही है।"

– नरेन्द्र मोदी

1. **34 करोड़ 43 लाख गरीब परिवारों के बैंक खाते खोले गए–** देश के करोड़ों गरीब परिवारों को मुख्यधारा के अर्थतंत्र से जोड़ने के लिए जन-धन योजना के अंतर्गत यह खाते खोले गए। इन खातों में 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जमा हुई है।

2. **1 करोड़ 53 लाख से अधिक घरों का निर्माण हुआ –** प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश में इन घरों का निर्माण हुआ है जिन्हें बेघर गरीबों के लिए स्वीकृत किया जा रहा है ।

3. **जन औषधि केंद्र –** प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत देश में 5,000 से अधिक जन औषधि केन्द्र खोले गए हैं जिनके माध्यम से जन सामान्य को 90% तक सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

4. **10 करोड़ परिवारों का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा –** आयुष्मान भारत के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों का 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कराया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत अभी तक 14500 से अधिक अस्पतालों का चयन किया गया है जहां असाध्य बीमारियों से ग्रस्त लोग अपना इलाज कराकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

5. **14 करोड़ 64 लाख लोगों का दुर्घटना बीमा –** प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मात्र 12 रुपये प्रति वर्ष देकर इतने लोगों का बीमा करवाया गया है।

6. **5 करोड़ 67 लाख परिवारों का जीवन बीमा –** प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपये प्रति वर्ष देकर इतने लोगों का बीमा करवाया गया है।

7. **9 करोड़ 74 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण –** स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इन शौचालयों का निर्माण किया गया है जिसके कारण स्वच्छता के साथ-साथ गरीब महिलाओं को शर्मसार होने से मुक्ति मिली है।

8. **समूचे देश में अन्न सुरक्षा योजना का लाभ–** देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल दिया जा रहा है।

9. **आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण –** एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए और दशकों से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए संविधान में संशोधन करके सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं को सरकारी नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

10. **सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे गरीब के खाते में–** 437 योजनाओं के लाभान्वित लोगों को 6 लाख 6 हजार 473 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे उनके खातों में भेजी जा चुकी है। इसके कारण बिचौलियों की दलाली से उन्हें मुक्ति मिली है।

11. **देश के हर गांव में बिजली पहुंची –** दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत सभी गांवों में यह बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर दिया गया है।

12. **2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा घरों में बिजली पहुंची –** गांवों में बिजली पहुंचाने के बाद घरों में बिजली पहुंचाने का कार्य शुरू किया गया है। सौभाग्य योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिए गए हैं।

युवा- हमारा भविष्य

"युवा कलेक्टिविटी, कनेक्टिविटी और क्रिएटिविटी पर ध्यान दें, क्योंकि देश के युवा ही देश को नई दिशा दे सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ऐसे युवाओं का निर्माण करना चाहते थे, जिनमें बिना भेद-भाव के एक दूसरे के प्रति प्रेम व विश्वास हो। युवा वह होता है, जो बिना अतीत की चिंता किए अपने भविष्य के लक्ष्यों की दिशा में काम करता है। आप सभी युवा जो काम आज करते हैं, वही तो कल जाकर देश का भविष्य बन जाता है।"

– नरेंद्र मोदी

हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु का है। यही युवा शक्ति हमारी ऊर्जा है। उनकी क्षमता का उपयोग करने के लिए मोदी सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनकी एक झलक यहां प्रस्तुत है :

1. **स्वरोज़गार हेतु 16 करोड़ से अधिक ऋणों का वितरण–** स्वरोजगार हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत 16 करोड़ लोगों को 7 लाख 74 हजार करोड़ रुपये की धनराशि का वितरण किया गया है।

2. **स्वरोज़गार के लिए स्टार्ट-अप–** स्वरोज़गार के लिए अब तक 15,649 स्टार्ट-अप्स को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इन सभी स्टॉर्ट-अप्स को 7 साल के ब्लॉक में लगातार 3 वर्षों तक टैक्स में राहत दी जाएगी।

3. **देशभर में एम्स, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी जैसे संस्थानों की स्थापना–** 14 नए एम्स, 14 नए ट्रिपल आईटी, 7 नई आईआईटी, 7 नए आईआईएम, एक नई एनआईटी, 103 नए केंद्रीय विद्यालय तथा 62 नए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है, ताकि हमारे युवा विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर सकें और अच्छे संस्थानों में रोज़गार प्राप्त कर सकें।

4. **प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों (PMKVY) की स्थापना–** युवाओं को 375 ट्रेड्स में प्रशिक्षित करने हेतु देश के हर जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त कर तथा मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण लेकर युवक तथा युवतियां अपना रोज़गार प्रारंभ कर रहे हैं।

5. **प्रतिभाशाली युवाओं को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप–** इस योजना के अंतर्गत प्रतिभाशाली युवाओं को 5 वर्ष तक 70,000-80,000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृति और शोध के लिए 2 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक अनुदान दिया गया है।

6. **खेलो इंडिया–** यह कार्यक्रम भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत हमारे देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के खिलाड़ियों, विशेषकर युवा खिलाड़ियों, को निर्बाध रूप से एक व्यापक और मज़बूत व्यवस्था प्रदान करके खेलकूद के क्षेत्र में भारत को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

7. **अटल टिंकरिंग लैब्स को स्वीकृति–** 60 लाख से अधिक छात्रों को अभिनव कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कूलों में 5,441 अटल टिकरिंग लैब्स को स्वीकृति प्रदान की गई है।

8. **प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता–** इस योजना के अंतर्गत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्ष तक 5 लाख रुपये वार्षिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

मध्यम वर्ग समाज की रीढ़

"यह मध्यम वर्ग की उदारता और उनकी ईमानदारी ही है, कानून को मानकर चलने की उनकी प्रतिबद्धता ही है जिसकी वजह से देश को टैक्स मिलता है, देश की योजनाएं बनती हैं और गरीब का कल्याण होता है। वर्षों से यह मांग रही है कि पांच लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त घोषित किया जाए। इतने वर्षों से की जा रही इस मांग को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है।"

– नरेंद्र मोदी

1. **आयकर छूट सीमा में वृद्धि–** मध्यम वर्ग को सबसे बड़ी राहत देते हुए पहली बार आयकर छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है।

2. **जीएसटी–एक राष्ट्र एक कर–** जीएसटी के लागू होने से विभिन्न करों के जंजाल से मुक्ति मिली है, हज़ारों चुंगी–नाके भी बंद हुए हैं। इससे व्यापार भी आसान हुआ है।

3. **महंगाई दर में कमी–** खुदरा महंगाई दर जनवरी 2019 में 2.05% दर्ज की गई, जो पिछले 19 महीनों में सबसे कम है।

4. **हार्ट स्टेंट के दामों में कमी–** हार्ट स्टेंट के दाम 85% तक कम होने से मरीजों को सालना 46,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। इसके अतिरिक्त घुटना प्रत्यारोपण की कीमत में 69% कमी होने से मरीजों को सालना 1500 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

5. **जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं–** इस योजना के अंतर्गत देशभर में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 5,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों पर 800 से अधिक दवाएं बहुत कम दामों पर उपलब्ध हैं।

6. **हवाई यात्रा हुई सस्ती–** उड़ान योजना के तहत हवाई यात्रा को सस्ता बनाया गया है। मात्र 2,500 रुपए में अनेक क्षेत्रों में हवाई यात्रा की सुविधा दी जा रही है।

7. **मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋणों को स्वीकृति–** इस योजना में 16 करोड़ से अधिक गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को 7 लाख 74 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि ऋण के रूप में वितरित की गई है।

8. **सातवां वेतन आयोग–** सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया है जिसके तहत न्यूनतम मूल वेतन 7 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 18 हज़ार निर्धारित कर दिया गया है। इससे लगभग 35 लाख सिविल कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

9. **मकान किराया भत्ता (HRA) एवं यातायात भत्ता (Transport Allowance)–** सातवें वेतन आयोग में मकान किराया भत्ता एवं यातायात भत्ता बढ़ा दिया गया है। मकान किराया भत्ता मूल वेतन का 24 प्रतिशत कर दिया गया है जो महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत हो जाने के पश्चात् और बढ़कर 27 प्रतिशत हो जाएगा। यह एक नई पहल शुरु की गई है।

10. **राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) सरकारी अंशदान में वृद्धि–** एनपीएस में सरकार ने 01.04.2019 से अपना अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। कर्मचारी का अंशदान 10 प्रतिशत ही रहेगा। इससे कर्मचारियों की पेंशन निधि में अधिक धन संचित हो पाएगा।

11. **न्यूनतम पेंशन–** सरकार ने न्यूनतम पेंशन को 3500 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है जिससे लाखों पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचा है।

12. **ग्रेच्युटी–** ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। इस पहल से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उपदान में अधिक धन मिलेगा, जिससे उनका भविष्य अधिक सुखमय हो जाएगा।

13. **सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन की विसंगतियां दूर–** एक जनवरी, 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के वेतन नए वेतनमानों में निर्धारित करके पेंशन दी जा रही है। इससे तिथि से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों तथा इसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन की विसंगतियों को दूर कर दिया गया है।

14. **मकान हेतु ऋण में प्रोत्साहन–** मकान हेतु लिए गए ऋण पर लगने वाले ब्याज़ की सीमा को आयकर से छूट के लिए डेढ़ लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। आयकर की धारा 80 से आवासीय ऋण की राशि की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दिया गया है।

15. **प्रधानमंत्री वय वंदन योजना–** इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले नागरिकों के लिए जमा पूंजी को भविष्य में होने वाली ब्याज़ दर की गिरावट से बचाने के लिए एक योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत 10 सालों के 8 प्रतिशत ब्याज़ दर निर्धारित कर दी गई है। बाजार की ब्याज़ दर में आई गिरावट और 8 प्रतिशत ब्याज़ दर के बीच के अंतर को सरकार वहन करेगी। 28.01.2019 तक 3 लाख 43 हज़ार 295 लाभार्थियों ने इस योजना में 21 हज़ार 757 करोड़ रुपए निवेश किए।

16. **वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष–** सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत बीमा कंपनियों में ऐसी राशि जिसपर पिछले 10 वर्षों से किसी के द्वारा दावा नहीं किया गया है, वह वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2018 तक 81 करोड़ 63 लाख रुपए इस कोष में स्थानांतरित कर दिए गए हैं जिसे वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

17. **जीवन प्रमाणपत्र अब ऑनलाइन भी–** वरिष्ठ नागरिकों को अपनी पेंशन को जारी रखने के लिए प्रतिवर्ष एक जीवन प्रमाणपत्र देना पड़ता है जिसमें देरी हो जाने से पेंशनभोगियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सरकार की नवीन पहल से अब यह जीवन प्रमाणपत्र किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन कराया जा सकता है। एक नवंबर, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 तक इस पहल के अंतर्गत 11 लाख से अधिक पेंशनभोगियों ने अपने जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाइन दाखिल किए हैं।

छोटे उद्यमी स्वदेशी के ध्वजवाहक

"छोटे उद्योग हमारे देश में बड़ी जनसंख्या को रोजगार देते हैं और अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं। एमएसएमई देश की प्रगति को गति देने का काम करते हैं। कढ़ाई-बुनाई से लेकर दवाई तक, खेत खलिहान से लेकर खेल के मैदान तक, वस्त्र से लेकर शस्त्र तक अनेक क्षेत्रों में लघु उद्योग अपना अहम योगदान देते रहे हैं।"

– नरेन्द्र मोदी

छोटे उद्यमी सबसे ज्यादा रोज़गार का निर्माण करते हैं। उनके इस महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के पर्व पर छोटे उद्यमियों को कुछ उपहार दिए :

1. **एमएसएमई सेक्टर के लिए 59 मिनट में लोन स्वीकृति–** एमएसएमई सेक्टर के लिए एक करोड़ रुपये तक के लोन की स्वीकृति अब एक घंटे से भी एक मिनट कम में की जाती है।

2. **छोटे उद्यमियों के लिए जीसटी छूट सीमा में बढ़ोतरी–** छोटे उद्यमियों को राहत देते हुए जीएसटी में छूट की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख किया गया है।

3. **तकनीक उन्नयन हेतु 'हब एंड स्पोक' की स्थापना–** एमएसएमई को तकनीकी सहायता के लिए 'हब एंड स्पोक' की स्थापना की गई है जिसके अंतर्गत देशभर में 20 केंद्रों (हब्स) और 100 टूलरूम्स (स्पोक्स) की स्थापना की जाएगी।

4. **साल में एक बार ही रिटर्न भरने की सुविधा–** इसके अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र में सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाते हुए 8 श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत दिया जाने वाला रिटर्न अब साल में दो बार की जगह एक बार ही देने की सुविधा प्रदान की गई है।

5. **निवारण प्रक्रिया को आसान बनाना–** इसके अंतर्गत एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को अब छोटी-छोटी गलतियों को सुधारने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। अनजाने में हुए छोटे उल्लंघन के लिए संबंधित विभाग में जाकर, कुछ आसान प्रक्रियाओं के माध्यम से उसमें सुधार किया जा सकता है।

6. **केंद्रीय कंपनियों के लिए 'जीइएम' (GeM) की सदस्यता अनिवार्य–** केंद्र सरकार की सभी कंपनियों के लिए 'जीइएम' (GeM) की सदस्यता लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कंपनियां अपनी सभी वेंडर एमएसएमई को भी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराएंगी, और उन्हें अपनी जरूरत का 25% माल छोटे उद्यमियों से खरीदना अनिवार्य होगा।

7. **बढ़ाई गई खरीद में महिला उद्यमियों के लिए आरक्षण–** सरकारी कंपनियों द्वारा एमएसएमई में बढ़ाई गई कुल खरीद का 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित किया गया है।

8. **फार्मा कंपनियों को क्लस्टर बनाने का निर्णय–** एमएसएमई सेक्टर की फार्मा कंपनियों को आसानी से बिजनेस करने के लिए क्लस्टर बनाने का फैसला लिया गया है जिनकी स्थापना से होने वाले खर्च का 70% भारत सरकार वहन करेगी।

महिला सशक्तिकरण

"हम उस परंपरा का हिस्सा हैं, जहां पुरुषों की पहचान नारियों से होती थी। यशोदा नंदन, कौशल्या-नंदन, गांधारी पुत्र, यही पहचान होती थी किसी बेटे की। आज सामाजिक, आर्थिक जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित करना हम सबका कर्तव्य है। नारी शक्ति ने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने खुद के साथ ही और समाज को भी आगे बढ़ाने और एक नए मुकाम पर ले जाने का काम किया है। आखिर हमारा 'न्यू इंडिया' का सपना यही तो है।"

– नरेंद्र मोदी

अजन्मी बेटी से लेकर महिला के बुढ़ापे तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके कल्याण की योजनाएं बनाई हैं। उनकी एक झलक यहां प्रस्तुत है :

1. **'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान' –** कन्या भ्रूण हत्या हमारे लिए एक अभिशाप है। गर्भ में बेटी का पता लगते ही गर्भपात करा देने से सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान' चलाया। यह एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक अभियान है। इसके परिणामस्वरूप 104 जिलों में लड़कियों की जन्मदर में बहुत बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा का उदाहरण तो बहुत सुखद है, जहां 1,000 लड़कों की तुलना में 883 लड़कियाँ पैदा होती थीं। अब यह संख्या बढ़कर 914 हो गई है।

2. **सुकन्या समृद्धि योजना –** इस योजना में बेटियों की शिक्षा से लेकर विवाह तक की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत एक करोड़ 30 लाख खाते खोले जा चुके हैं।

3. **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मुफ्त शिक्षा और छात्रावास–** कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में गरीब परिवार की बेटियों को कक्षा 12 तक मुफ्त शिक्षा और छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

4. **गर्भवती महिलाओं का रक्षण–** प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत 13,161 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक करोड़ 70 लाख से अधिक प्रसवपूर्व चेक-अप के साथ ही 86 लाख 88 हजार गर्भवती महिलाओं का रक्षण किया गया है।

5. **गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता –** प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत हर वर्ष 50 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है।

6. **महिला कामगारों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि में वृद्धि–** महिला कामगारों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाकर 26 सप्ताह (6 महीने) कर दी गई है ताकि वे अपने नवजात शिशु की अच्छी तरह देखभाल कर सकें। 49 लाख 88 हजार महिलाओं को मातृत्व लाभ के लिए 01 लाख 678 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

7. **गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन –** प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं की जिन्दगी आसान करने तथा धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए के 6 करोड़ 26 लाख महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन बांटे गए हैं।

8. **स्वरोज़गार के लिए ऋण की सुविधा–** महिला कामगारों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण देने की व्यवस्था की गई है। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 16.5 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 72.25 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को मिले हैं।

9. **राशन कार्ड महिला के नाम पर–** एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर यह तय किया गया है कि महिला को परिवार की मुखिया मानकर राशन कार्ड उसके नाम पर ही बनाया जाएगा।

10. **स्टैंप ड्यूटी में राहत–** यदि जायदाद महिला के नाम पर होगी तो स्टैंप ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

11. **स्टैण्ड-अप योजना–** इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 10 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है। देश के हर बैंक की हर शाखा को यह निर्देश दिया गया है कि उसके द्वारा कम-से-कम एक महिला को यह ऋण अनिवार्य रूप से दिया जाए।

12. **बढ़ाई गई खरीद में महिला उद्यमियों के लिए आरक्षण–** सरकारी कंपनियों द्वारा एमएसएमई में बढ़ाई गई कुल खरीद का 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित किया गया है।

13. **अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति–** पिछले साढ़े चार वर्षों में अल्पसंख्यक समुदायों के लगभग 3 करोड़ 83 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इसमें लगभग 60 प्रतिशत छात्राएं हैं।

14. **भारतीय वायु सेना में लड़ाकू पायलट के रूप में अब महिलाएं भी–** इंडियन एयर फोर्स में पहली बार भारतीय महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पायलट के रूप में शामिल किया गया है।

15. **आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में डेढ़ गुना वृद्धि–** देश भर में 27 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में डेढ़ गुना वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के बाद अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाने वाला मानदेय इस प्रकार है:

क्र.सं.	कार्यकर्ता श्रेणी	पुराना मानदेय (₹)	नया मानदेय (₹)
1	आंगनबाड़ी सेविका	3000	4500
2	मिनी आंगनबाड़ी सेविका	2250	3500
3	आंगनबाड़ी सहायिका	1500	2250

16. **12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के बलात्कार के दोषी को मौत की सजा–** एक कानून बनाकर 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के बलात्कार के दोषी को मौत की सजा का प्रावधान किया गया है तथा 16 वर्ष से कम उम्र की किशोरी के साथ बलात्कार के दोषी की न्यूनतम सजा 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है।

17. **ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण–** तीन तलाक को अपराध बनाने तथा मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने वाला विधेयक लोकसभा में पारित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम महिलाओं को पुरुष अभिभावक के बिना हज पर जाने के लिए भी अनुमति प्रदान की गई है।

18. **पासपोर्ट नियमों में संशोधन द्वारा तलाकशुदा महिलाओं को राहत–** पासपोर्ट नियमों में संशोधन करके तलाकशुदा महिलाओं के अपने पूर्व पति का नाम न लिखने की छूट दे दी गई है जिसके कारण उन्हें मानसिक यातना से राहत मिली है।

19. **अनिवासी भारतीय (NRI) विवाह विधेयक राज्य सभा में पेश–** अनिवासी भारतीय (NRI) पुरुषों द्वारा विवाहित महिलाओं को छोड़ने, प्रताड़ित करने और मानसिक यातना देने के मामलों का निराकरण करने तथा दोषी पतियों को सज़ा दिलाने के संबंध में विदेश मंत्रालय द्वारा एक विधेयक राज्य सभा में पेश किया गया है।

20. **इंटीग्रेटेड नोडल एजेंसी का गठन–** राज्य सभा में विधेयक पेश करने के अलावा 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' के अंतर्गत एक प्राधिकरण (Authority) का गठन किया गया है, जिसकी सिफारिश तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विदेश मंत्रालय द्वारा ऐसे 40 दोषी पतियों के पासपोर्ट निलंबित किए गए हैं एवं 21 अन्य स्थायी रूप से रद्द कर दिए गए हैं।

श्रमिक श्रमेव जयते

"यह शर्ट पैसों से नहीं निकलती हैं। अच्छी साड़ी हो, शर्ट हो, कपड़े हो, किसी न किसी ग़रीब के परिश्रम का परिणाम हैं और इस लिए समाज के इस श्रमिक वर्ग के प्रति उस संवेदना के साथ, उस ग़रीब के साथ अगर देखना हमारा स्वभाव बनता हैं, तो मुझे विश्वास है कि सच्चे अर्थ में यह श्रमयोगी राष्ट्रयोगी बनेगा। ये श्रमयोगी राष्ट्र निर्माता बनेगा।"

– नरेंद्र मोदी

1. असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मानधन– असंगठित क्षेत्र के कामगार यानी स्वयं मेहनत मज़दूरी करके अपने परिवारों को पालने का काम कर रहे लोगों के लिए एक ऐतिहासिक 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन योजना' बनाई गई है। इस योजना के माध्यम से इन कामगारों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु होती है, तो उसे मिलने वाली पेंशन की 50 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी के जीवनसाथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी।

2. न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि– मोदी सरकार द्वारा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो अब तक की सबसे ज्यादा है।

3. श्रमिकों की बोनस सीमा में वृद्धि– श्रमिकों को मिलने वाले वार्षिक बोनस को अब दोगुना करके 3500 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये कर दिया गया है जो अब तक का सबसे ज्यादा है।

4. श्रम सुविधा पोर्टल – इस पोर्टल को श्रम से जुड़े कानूनों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए विकसित किया गया है।

5. न्यूनतम पेंशन का निर्धारण– पहले श्रमिकों को 50 या 100 रुपए भी पेंशन मिला करती थी। मोदी सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी कर्मचारी को 1000 रुपए से कम पेंशन नहीं दी जाएगी। इसलिए सभी को कम से कम 1000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन सुनिश्चित कर दी गई है।

6. मनरेगा के बजटीय आवंटन में वृद्धि– वर्ष 2018–19 में मोदी सरकार ने मनरेगा की धनराशि को बढ़ाकर 55 हजार करोड़ रुपए कर दिया है तथा सरकार अब मजदूरी की राशि हर 15 दिन बाद मजदूरों के बैंक खाते में सीधे डालती है।

7. मजदूरी का इलेक्ट्रॉनिक और चेक के माध्यम से भुगतान – श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देते हुए उनकी मजदूरी का भुगतान चैक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने का प्रावधान किया गया है।

8. यूनिक प्रोविडेंट फंड खाते का आरंभ– सरकार द्वारा प्रत्येक श्रमिक को प्रोविडेंट फंड का यूनिक खाता प्रदान किया गया है। अब फंड की बचत राशि नौकरी बदलने के बाद भी नए रोजगार के रूप में मिलेगी।

9. दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय कामगार शिक्षा और विकास बोर्ड – इस बोर्ड द्वारा संगठित, असंगठित व मनरेगा कामगारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

समृद्ध किसान - समृद्ध राष्ट्र

"हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि हमारे मेहनती किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाए। इसके लिए हम जहां भी आवश्यक हो, उन्हें उचित सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमें किसानों पर विश्वास है। वे जोखिम लेने और बेहतर परिणाम लाने के लिए तैयार हैं!"

– नरेंद्र मोदी

1. **लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य–** पहली बार किसानों को उनकी रबी और खरीफ की फसलों का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत का ड़ेढ़ गुना घोषित किया गया है, जिसके कारण उन्हें अपनी फसल की अच्छी कीमत प्राप्त हो रही है।

2. **प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को सम्मान –** प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में पहली बार 5 एकड़ तक भूमि वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

3. **ई–नैम प्लेटफार्म के माध्यम से फसलों की सीधी बिक्री–** किसान अपना माल जिस मंडी में सबसे ज्यादा भाव या दाम मिल रहा हो उसमें बेच सकें और सस्ते में अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर न हों, इसलिए 585 मंडियों को ई–नैम के अंतर्गत जोड़ा गया है जिसके माध्यम से किसान सर्वाधिक मूल्य पर अपनी फसलें बेच रहे हैं।

4. **नीम कोटेड यूरिया –** यूरिया की कालाबाजारी को रोकने और किसानों को यूरिया सहजता से उपलब्ध कराने के लिए 100% यूरिया की नीम कोटिंग करवाई गई है, इसके कारण किसान को समय पर और पर्याप्त मात्रा में बिना किसी परेशानी के यूरिया मिल पा रहा है।

5. **कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बजट में सर्वाधिक राशि का आवंटन–** कृषि क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए और किसानों को फसल का उचित मूल्य मिले, फसल बर्बाद होने पर पर्याप्त मुआवजा मिले, इसलिए पिछले पांच वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 2 लाख 11 हजार 694 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया, है जो अब तक का सबसे ज्यादा है।

6. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हेतु बजटीय आवंटन में 16.21% की वृद्धि–** इस योजना के अंतर्गत 'पर ड्राप मोर क्रॉप (बूंद–बूंद से फले फसल)' के माध्यम से हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 5 हजार 460 करोड़ रुपये की धनराशि का बजटीय आवंटन किया गया, जो अब तक का सबसे ज्यादा है।

7. **प्राकृतिक आपदा से अधिक सुरक्षा–** पहले किसानों को प्राकृतिक आपदा से 50 प्रतिशत फसल बर्बाद होने पर ही आर्थिक सहायता मिला करती थी किंतु अब 33 प्रतिशत का नुकसान होने पर ही यह सहायता दी जा रही है। इसके कारण किसानों को दी गई कुल राहत राशि में 6 गुना वृद्धि हुई है।

8. **18 करोड 41 लाख मिट्टी जांच कार्ड (Soil Health Card) का वितरण–** किसानों की ज़मीन की मिट्टी की जांच के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड योजना बनाई गई है। मिट्टी की इस जाँच के कारण किसानों को ज्यादा फसल लेने के लिए सही सलाह मिल रही है।

9. **वार्षिक दूध उत्पादन में 49% की वृद्धि–** डेयरी किसानों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण दुग्ध उत्पादन की वार्षिक दर में पिछले पांच वर्षों में लगभग 49% की बढ़ोतरी हुई है।

10. **दलहन–तिलहन की खरीद में महत्वपूर्ण वृद्धि–** भाजपा सरकार के पांच वर्षों में 78 लाख 61 हजार मीट्रिक टन दलहन–तिलहन की खरीद की गई जो अब तक की सबसे ज्यादा खरीदी है।

11. **मछली उत्पादन में 42.22% वृद्धि–** पिछले वित्त वर्ष के दौरान मछली के उत्पादन में 42.22% वृद्धि दर्ज की गयी है। इस दिशा में भारत की निर्यात क्षमता में भी 180% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।

12. **दुग्ध उत्पादकों, पशुपालकों तथा मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड–** पहले किसान क्रेडिट कार्ड केवल खेती करने वालों को ही दिया जाता था लेकिन अब दुग्ध उत्पादकों, पशुपालकों तथा मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है।

13. **बांस को काटने की अनुमति–** भारतीय वन अधिनियम, 2017 में संशोधन करके बांस को अब वृक्ष की श्रेणी से निकालकर घास की श्रेणी में डाल दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अब बांस को काटने एवं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसानों को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके कारण पूर्वोत्तर के किसानों की किस्मत ही बदल गई है और अन्य राज्यों के किसानों को भी अतिरिक्त आमदनी का जरिया मिल गया है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का उत्थान

"हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें बाबा साहब से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थ के तौर पर विकसित करने का अवसर मिला है। महू में बाबा साहेब की जन्मभूमि, लंदन में डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल– उनकी शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई में चैत्य भूमि, दिल्ली में उनकी महापरिनिर्वाण भूमि। ये ही हैं हमारे पंचतीर्थ।"

–नरेंद्र मोदी

1. **अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के कल्याण हेतु बजटीय प्रावधान–** अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों के कल्याण हेतु 95 हजार करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है।

2. **पंचतीर्थ योजना–** हमारे संविधान निर्माता डॉ. अम्बेडकर के प्रति अनूठी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मोदी सरकार ने डॉ. अम्बेडकर से जुड़े पांच स्थानों को पंचतीर्थ मानकर नया निर्माण करवाया है।

3. **स्टैंड अप योजना–** अनुसूचित जाति, जनजाति के युवाओं को उद्योग लगाने के लिए स्टैंड अप योजना बनाई गई है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 10 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए का ऋण दिया जाता है। देश के हर बैंक की हर शाखा को यह निर्देश दिया गया है कि उसके द्वारा कम–से–कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को यह ऋण अनिवार्य रूप से दिया जाए।

4. **छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा में वृद्धि–** अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के पात्र छात्रों को छात्रवृति के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर ढाई लाख रुपए कर दिया गया है।

5. **छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि–** पिछले 5 वर्षों के दौरान 5 करोड़ 7 लाख एससी/एसटी छात्रों को 15,918 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति का लाभ मिला है।

6. **जनजातीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना–** भाजपा सरकार द्वारा जनजातियों की विरासतों को संरक्षित करने हेतु उनकी पारंपरिक संस्कृति, कलाओं और बोली–भाषाओं के प्रोत्साहन और संवर्द्धन संबंधी गतिविधियों के लिए विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

7. **अंतर–जातीय विवाह के लिए सम्मान राशि–** अंतर–जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग में विवाह करने पर ढाई लाख रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत 71,387 वैवाहिक जोड़ों को 219 करोड़ 4 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

8. **सशक्त एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम–** अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को संविधान में संशोधन करके और अधिक सशक्त बनाया गया है।

9. **विशेष अदालतों की स्थापना –** एससी/एसटी समुदायों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की गई है।

10. **अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि–** अनुसूचित जाति के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 50 लाख रुपए से 15 करोड़ रुपए तक की राशि का ऋण प्रदान करने के लिए वेंचर कैपिटल योजना (Venture Capital Scheme) शुरु की गई है। इसमें ब्याज़ दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत 322 करोड़ 8 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

11. **एकलव्य मॉडल विद्यालयों की स्थापना–** इस योजना के तहत 288 एकलव्य मॉडल विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं तथा पिछले पांच वर्षों में 2751 करोड़ रुपए राज्य सरकारों को दिए गए हैं।

12. **कौशल विकास योजना–** इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 102 करोड़ 54 लाख रुपए की धनराशि व्यय की गई है। अब तक एक लाख 7 हज़ार 246 अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारी वर्ग के व्यक्तियों को इसका लाभ मिला है।

13. **खेलों के लिए आधारभूत ढ़ांचे का विकास–** इसके अंतर्गत देश के 163 जिले जिनमें आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां सरकार खेलों से संबंधित आधारभूत ढ़ांचे का विकास कर रही है।

14. **प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना–** इसके अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले चिन्हित 2,500 गांवों के विकास के लिए 530 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

15. **विदेश अध्ययन हेतु नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना–** इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष चयनित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 की गई है। इस सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित जाति वर्ग के 484 छात्र/छात्राओं को वदेश अध्ययन हेतु नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 39 करोड़ 87 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

दिव्यांग हमारे विशिष्ट नागरिक

"शब्दों का अपना महत्व होता है... परमात्मा ने जिसको शरीर में कुछ कमी दी है, हम उसे विकलांग कहते हैं। कभी-कभी हम जब उनसे मिलते हैं तो पता चलता है कि हमें आंखों से उनकी यह कमी दिखती है, लेकिन ईश्वर ने उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पावर दिया होता है। एक अलग शक्ति का उनके अंदर परमात्मा ने निरूपण किया होता है। मेरे मन में विचार आया कि क्यों न हम देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग करेंगे। ये वे लोग हैं, जिनके पास एक ऐसा अंग है या एक से अधिक अंग हैं , जिनमें दिव्यता है!"

— नरेंद्र मोदी (मन की बात से उद्धृत)

शरीर के किसी एक अंग से बाधित व्यक्ति को दिव्यांग शब्द की संज्ञा देकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी संवेदनशीलता प्रकट करते हुए उन्हें सम्मान दिया है :

1. **दिव्यांगजन के कल्याण हेतु दिव्यांगताओं के प्रकार में वृद्धि–** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के माध्यम से पूर्व में 7 प्रकार की दिव्यांगताओं के स्थान पर 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है।

2. **दिव्यांगजन के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण में वृद्धि–** दिव्यांगजनों के अधिकतम कल्याण हेतु दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण को पूर्व में दिए जा रहे 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है।

3. **कॉलजों और व्यावसायिक संस्थाओं में दिव्यांगजन के लिए आरक्षण में वृद्धि–** दिव्यांगजन के लिए कॉलेजों और व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण में वृद्धि करते हुए 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

4. **एडिप–** इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में 7,800 से अधिक शिविर आयोजित किए गए जिसमें 12 लाख 40 हजार दिव्यांगजन को 737 करोड़ 51 लाख रुपए का लाभ हुआ है। इस दौरान 6 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं।

5. **कॉक्लियर इंप्लांट ऑपरेशन–** इस योजना के अंतर्गत ऑपरेशन कराने हेतु प्रत्येक दिव्यांगजन को 6 लाख रुपए सहायता राशि का अनुदान दिया जाता है। 186 अस्पतालों को कॉक्लियर इम्लांट ऑपरेशन के लिए पैनलबद्ध किया है। अब तक 1,706 एडिप कॉक्लियर इम्पलांट ऑपरेशन हो चुके हैं। जिनके कारण बधिर दिव्यांगों को सुनने की क्षमता प्राप्त हुई है।

6. **मैट्रिकपूर्व और मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति–** इस योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में 17 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि जारी की गई है जिससे 24,545 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा 11 और मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति हेतु 60 करोड़ 62 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है जिससे 31,448 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए हैं।

7. **दिव्यांगजन के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना–** इसके अंतर्गत 266 संगठन प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं। वर्ष 2014-15 से एक लाख 58 हजार 468 दिव्यांगजन के कौशल प्रशिक्षण के लिए 174 करोड़ 48 लाख रुपए का सहायता अनुदान जारी किया गया है।

8. **दिव्यांगता खेल केंद्र–** ग्वालियर में 170 करोड़ रुपए की लागत से एक दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित किया गया है।

9. **भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान केंद्र की स्थापना–** मूक एवं बधिर दिव्यांगजन की क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC) की स्थापना की गई है।

10. **दिव्यांग छात्रों के लिए रैम्प व रेलिंग और विशेष शौचालयों का निर्माण–** देशभर में दिव्यांग छात्रों की सुविधा के लिए 54,000 रैम्प व रेलिंग और 50,000 विशेष शौचालयों का निर्माण किया गया है।

11. **दृष्टि बाधित लोगों के अनुकूल सिक्के–** मोदी सरकार द्वारा दृष्टि बाधित लोगों के अनुकूल सिक्कों की नई श्रृंखला को जारी किया गया है। ये नए सिक्के दृष्टि बाधित लोगों के लिए सहायक होंगे तथा उनमें विश्वास की भावना भरेंगे।

12. **दिव्यांगजन को विशिष्ट पहचान पत्र जारी–** दिव्यांगजन का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए प्रत्येक दिव्यांगजन को एक विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया गया है। दिव्यांगजन को दी जाने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इस कार्ड की सुविधा दी गई है। अब तक देश के 500 जिलों में 15 करोड़ रुपए के व्यय से 13 लाख 23 हजार ऐसे विशिष्ट पहचान पत्र जारी किए गए हैं।

अल्पसंख्यक अब मुख्यधारा में

"इस देश का कोई भी शख्स चाहे मंदिर में दिया जलाता हो या मस्जिद में सजदा करता हो, गुरुद्वारे में सबद या चर्च में प्रार्थना करता हो, हमें सब पर गर्व है। हम सबको अपनी विविधता की विरासत पर गर्व है, साथ ही विरासत की विविधता पर भी हमें गर्व है।" –नरेंद्र मोदी

गरीबों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के गरीबों को भी दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाएं केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही बनाई गई हैं :

1. सीखो और कमाओ, उस्ताद, नई मंजिल , गरीब नवाज कौशल विकास योजना जैसी रोज़गारपरक तथा कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से लगभग 7 लाख 50 हजार युवाओं को कौशल विकास तथा रोज़गार के अवसर मुहैया कराए गए। इनमें लगभग 50 प्रतिशत लड़कियां शामिल हैं।

2. हुनर हाट के माध्यम से पिछले दो वर्षों में 2 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों/शिल्पकारों को न केवल रोज़गार तथा रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए गए, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय बाजार में अवसर भी मुहैया कराए गए हैं।

3. विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति– पिछले लगभग 4 वर्षों में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं से अल्पसंख्यक समाज के गरीब व कमज़ोर लगभग 2 करोड़ 95 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं, जिसमें लगभग 60 प्रतिशत छात्राएं शामिल हैं।

4. लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर में कमी– मोदी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम लड़कियों के स्कूल छोड़ देने की दर जो पहले 70–72 प्रतिशत थी, वह अब घटकर लगभग 35 प्रतिशत रह गई है। हम इसे शून्य प्रतिशत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

5. नई रोशनी योजना के तहत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को विभिन्न तरह का कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसके जरिए वे तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं।

6. मदरसा शिक्षकों को प्रशिक्षण– वर्ष 2018 में मदरसा शिक्षकों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

7. वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण– मोदी सरकार के इस अभियान के तहत 90 प्रतिशत वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।

8. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल– सभी छात्रवृत्तियां, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से 'डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT)' के जरिए सीधे छात्र–छात्राओं के बैंक खातों में भेजी जा रही हैं।

9. ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण– तीन तलाक को अपराध बनाने वाला विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है।

10. मुस्लिम महिलाओं को बिना पुरुष अभिभावक के हज पर जाने की अनुमति– अब मुस्लिम महिलाएं बिना किसी पुरुष अभिभावक को साथ लिए हज के लिए जा सकती हैं।

11. हज कोटे में वृद्धि– वर्ष 2014 में हज कोटा एक लाख 36 हजार हाजियों के लिए था, जो हमारे कार्यकाल में बढ़ते–बढ़ते अब 2 लाख हाजियों के लिए हो गया है। वर्ष 2019 में आजादी के बाद पहली बार रिकॉर्ड 2 लाख भारतीय मुसलमान बिना 'सब्सिडी' के हज के लिए जाएंगे।

12. 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' के द्वारा विकास योजनाओं का विस्तार– पिछले लगभग साढ़े चार वर्षों के दौरान इस योजना के तहत 28 डिग्री कॉलेज, 2197 स्कूल भवन, 40201 अतिरिक्त क्लासरूम, 1213 हॉस्टल, 191 आईटीआई, 50 पॉलिटेक्निक, 39586 आंगनबाड़ी केंद्र, 348624 घर, 405 सद्भावना मंडप, 89 आवासीय स्कूल, 527 मार्किट शेड्स, 17397 पेयजल सुविधाओं का मोदी सरकार द्वारा अल्पसंख्यक क्षेत्रों में निर्माण कराया गया।

कृपया वोट देने से पहले सोचें

भारत जमीन का टुकड़ा नहीं,
जीता जागता राष्ट्रपुरुष है।
हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है,
पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं
पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघायें हैं।
कन्याकुमारी इसके चरण हैं,
सागर इसके पग पखारता है।
यह चन्दन की भूमि है,
अभिनंदन की भूमि है,
इसका कंकर–कंकर शंकर है,
इसका बिन्दु–बिन्दु गंगाजल है।
हम जिएंगे तो इसके लिये मरेंगे तो इसके लिये।
मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी
अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो
एक ही आवाज आयेगी भारत माता की जय।

– अटल बिहारी वाजपेयी

जो बालाकोट में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई पराक्रमी एयर स्ट्राइक को दलगत राजनीति के चश्मे से देखते हैं तथा सेना का मनोबल गिराते हैं, क्या वे आपके वोट के हक़दार हैं?

जो भद्दी भाषा में भारतीय सेना से प्रश्न करते हैं कि "आप लड़ने गए थे या पेड़ उखाड़ने" क्या वे आपके वोट के हक़दार हैं?

जो जम्मू–कश्मीर के अलगाववादियों का समर्थन करते हैं, क्या वे आपके वोट के हक़दार हैं?

जिन्होंने दस साल तक भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमानों से वंचित रखा, क्या वे आपके वोट के हक़दार हैं?

जो भारतीय सेना से उनके शौर्य का सबूत मांगते हैं, क्या वे आपके वोट के हक़दार हैं?

जो ओसामा बिन लादेन और हाफ़िज़ सईद जैसे ख़ूंख़ार आतंकियों को ओसामा जी और हाफ़िज़ साहब कहकर सम्बोधित करते हैं, क्या वे आपके वोट के हक़दार हैं ?

जिन्होंने भारतीय सेना को बुलेट प्रूफ़ जैकेट जैसी बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई, क्या वे आपके वोट के हक़दार हैं ?

जो "भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी" जैसे नारे लगाने वालों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, क्या वे आपके वोट के हक़दार हैं ?

जो भारत माता की जय का नारा लगाने से हिचकते हैं, क्या वे आपके वोट के हक़दार हैं?

जो भारत सरकार की बजाय पाकिस्तान की सरकार के बयानों पर भरोसा करते हैं, क्या वे आपके वोट के हक़दार हैं?

जो वन्दे मातरम गान का खुला विरोध करते हैं, क्या वे आपके वोट के हक़दार हैं?

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-19